

भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सुधार

यह एडिटरियल 19/12/2024 को द हट्टि में प्रकाशित “[Making affordable generics more reliable](#)” पर आधारित है। जेनेरिक दवाइयों भारत में कफायती स्वास्थ्य सेवा के लिये महत्वपूर्ण हैं, जिससे वर्ष 2024 तक ₹30,000 करोड़ की बचत होगी, लेकिन वखिंडति नियामक नगिरानी के कारण गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं। कई समितियों की सफिराशों के बावजूद, केंद्रीकृत वनियिमन की कमी वहनीयता और गुणवत्ता दोनों को सुनश्चिति करने के लिये व्यापक सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है।

प्रलिमिस के लिये:

जेनेरिक दवाएँ, केंद्रीय औषधि मानक नयितरण संगठन, फार्मास्यूटिकल वनियिमन, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य नरिधारण प्राधकिरण, TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलु), पेटेंट अधनियिम, 1970, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधनियिम, 1985, रोगाणुरोधी प्रतरीध, रैनबैक्सी घोटाला, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र

मेन्स के लिये:

भारत में फार्मास्यूटिकल वनियिमन की वर्तमान स्थिति, अपर्याप्त फार्मास्यूटिकल वनियिमन से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियाँ।

जेनेरिक दवाएँ भारत की स्वास्थ्य सेवा पहुँच के लिये महत्वपूर्ण हैं, जिससे वर्ष 2024 तक सरकारी पहलों के माध्यम से उपभोक्ताओं को अनुमानित ₹30,000 करोड़ की बचत हुई है। ब्रांडेड दवाओं के समतुल्य होने के बावजूद, इनकी गुणवत्ता की चिंता बनी हुई है। **केंद्रीय औषधि मानक नयितरण संगठन** और **राज्य औषधनियामक प्राधकिरणों** के बीच वभाजित वर्तमान नियामक फ्रेमवर्क नरिमाताओं को **कमजोर नगिरानी का फायदा उठाने** की अनुमति देता है, जिससे दवा की गुणवत्ता कमजोर होती है। वर्ष 1954 से कई समितियों की अनुशंसा के बावजूद, भारत में अभी भी केंद्रीकृत **फार्मास्यूटिकल वनियिमन** का अभाव है, जो इसके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सामर्थ्य और गुणवत्ता दोनों को सुनश्चिति करने के लिये व्यापक सुधार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

भारत में फार्मास्यूटिकल वनियिमन की वर्तमान स्थिति क्या है?

■ नियामक नकियाय

- **केंद्रीय औषधि मानक नयितरण संगठन (CDSCO):** वर्ष 1940 में स्थापति, CDSCO फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की देखरेख करने वाला प्राथमिक नियामक प्राधकिरण है।
 - यह सुनश्चिति करता है कि दवाएँ सौंदर्य प्रसाधन और चकितिसा उपकरण सुरक्षा मानकों को पूरा करें।
- **रसायन एवं पेट्रोरसायन वभाग:** वर्ष 1991 में स्थापति, **DCP रसायन, पेट्रोरसायन और फार्मास्यूटिकल्स के नीति एवं योजना पहलुओं का प्रबंधन** करता है तथा इस क्षेत्र के विकास में सहायता करता है।
- **राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य नरिधारण प्राधकिरण:** वर्ष 1994 में स्थापति NPPA मूल्य नरिधारण, संशोधन और मूल्य नयितरण के तहत दवाओं की सूची को अद्यतन करने के लिये जमिमेदार है।
 - यह सुनश्चिति करता है कि आवश्यक दवाओं की कीमतों को वनियिमति और नगिरानी की जाए।

■ प्रमुख नीतियाँ और वनियिमन

- **औषधि मूल्य नयितरण:** औषधि मूल्य नयितरण आदेश (DPCO), जिसे पहली बार वर्ष 1970 में लागू किया गया था, सरकार को 74 थोक औषधियों और उनके फॉर्मूलेशन के मूल्यों को वनियिमति करने की अनुमति देता है।
 - यद्यपि यह सामर्थ्य की गारंटी देता है, लेकिन **प्रत्यक्ष मूल्य प्रतबंध** उद्योग को इन दवाओं का उत्पादन करने से रोक सकता है।
- **उत्पाद की गुणवत्ता और वनरिमाण मानक:** CDSCO द्वारा **अच्छे वनरिमाण अभ्यास (GMP)** को लागू किया जाता है, ताकि यह सुनश्चिति किया जा सके कि **फार्मास्यूटिकल संयंत्र और सामग्री उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करें**।
 - **राष्ट्रीय औषधि नीति** का उद्देश्य GMP मानदंडों को और सख्त करना है।
- **पेटेंट और बौद्धिक संपदा वनियिमन:** **पेटेंट अधनियिम, 1970** (वर्ष 2005 में संशोधित) औषधियों की पेटेंट योग्यता को नयितरति करता है तथा रॉयल्टी, जेनेरिक उत्पादन प्रतरीक्षा, पेटेंट वरीध, अनविरय लाइसेंसिंग और नरियात के **प्रावधानों की रूपरेखा** तैयार करता है।
 - **TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलु)** नैदानिक परीक्षणों से संबंधित अधोषति जानकारी के लिये सुरक्षा

प्रदान करता है।

■ प्रमुख वनियामक दिशा-निर्देश

- औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940: भारत में औषधियों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है।
 - अनुसूची M: कुछ दवाओं के निर्माण में कारखाना परस्पर, सामग्री और उपकरणों के लिये सामान्य एवं वशिष्ट आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।
 - अनुसूची T: आयुर्वेदिक, सदिध और यूनानी दवाओं के वनिरमाण के लिये GMP वनिरदेश नरिधारति करता है।
 - अनुसूची Y: नैदानिक परीक्षणों के लिये वधिधी आवश्यकताओं को नरिधारति करती है।
- अच्छे नैदानिक अभ्यास (GCP) दिशा-नरिदेश: स्वास्थय मंतरालय, DCGI और ICMR द्वारा तैयार किये गए ये दिशा-नरिदेश, हेलसकि घोषणा एवं मानव उपयोग के फारमास्यूटिकल्स हेतु तकनीकी आवश्यकताओं के सामंजस्य के लिये अंतरराष्ट्रीय परषिद जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर, मानव वषियों में नैदानिक अनुसंधान को वनियमति करते हैं।
- फारमेसी अधिनियम, 1948: भारत में फारमेसी व्यवसाय को वनियमति करता है।
- औषधि एवं जादुई/चमत्कारी उपचार (आपत्तजनिक वजिजापन) अधिनियम, 1954: यह अधिनियम चमत्कारी गुणों का दावा करने वाली औषधियों के वजिजापन पर प्रतर्बिध लगाता है।
- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985: स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंघति कार्यों को वनियमति करता है।

अपर्याप्त फारमास्यूटिकल वनियमन से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- नमिन स्तरीय और नकली दवाओं का प्रसार: कमजोर प्रवर्तन के कारण नमिन गुणवत्ता वाली और नकली दवाएँ बाज़ार में प्रभावी हो जाती हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थय एवं मरीजों का वशिवास कमजोर होता है।
 - वशि्व स्वास्थय संगठन ने भारत में नरिमति कफ सरिप को गामबधिया में बचचों की तीव्र कडिनी फेलयिर और मृत्यु से संबध बताया है।
 - यह समस्या नमिन आय वाले देशों को असमान रूप से प्रभावति करती है, जहाँ नयामक नगिरानी न्यूनतम है, जिसके परणामस्वरूप रुग्णता और मृत्यु दर अधकि होती है।
 - भारत में, वनियामक खामियों के कारण छोटे नरिमाताओं के प्रभुत्व वाले खंडति बाज़ार में नमिन स्तरीय उत्पाद वकिसति हो रहे हैं।
 - वशि्व स्वास्थय संगठन का अनुमान है कनिमिन और मध्यम आय वाले देशों में 10% दवाइयाँ नमिन स्तरीय या नकली हैं।
- नरियात में अंतरराष्ट्रीय वशिवास का क्षरण: वैश्वकि मानकों का असंगत पालन नरियातक देशों की प्रतर्षिठा को नुकसान पहुँचाता है, जिससे वैश्वकि बाज़ारों में प्रतर्षिप्रदधात्मकता कम हो जाती है।
 - डाटा नरिमाण और अपर्याप्त गुणवत्ता जाँच सहति नयामक चूक, अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच वशिवास को कम करती है।
 - इससे भारत जैसे दवा नरियातक देशों के दीर्घकालकि आर्थकि लाभ में बाधा उत्पन्न होती है।
 - वर्ष 2022 की शुरुआत से अब तक भारतीय दवा नरिमाताओं को 9 से अधकि FDA चेतावनी पत्र जारी किये गए हैं, जिसके कारण अमेरिका में नए उत्पादों पर प्रतर्बिध लग सकता है।
 - रैनबेक्सी घोटाला अंतरराष्ट्रीय नयामक वफिलता का एक ऐतिहासकि मामला बना हुआ है।
- रोगाणुरोधी प्रतर्षिध (AMR) संकट: एंटीबायोटकि दवाओं का अनयिमति उत्पादन और अतार्ककि उपयोग AMR को बढ़ाने में योगदान देता है, जो एक गंभीर वैश्वकि स्वास्थय खतरा है।
 - AMR स्वास्थय देखभाल प्रणालियों को कमजोर करता है, क्योंकि सामान्य संक्रमण उपचार योग्य नहीं रह जाते, जिससे बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है।
 - कठोर नगिरानी के अभाव के कारण दवा कंपनयिँ पर्याप्त नैदानिक परीक्षणों के बनिा ही नशिचति खुराक वाले एंटीबायोटकि संयोजनों का उत्पादन कर लेती हैं।
 - एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कबिडी संख्या में भारतीय रोगियों को अनेक एंटीबायोटकि दवाएँ दी जाती हैं, जिसके कारण एंटीबायोटकि प्रतर्षिध उत्पन्न होता है।
 - भारत में बकिने वाली लगभग 64% एंटीबायोटकि असवीकृत हैं, जिससे प्रतर्षिध बढ़ रहा है।
- प्रतर्किल औषधि प्रतर्किरिया और फारमाकोवजिलिंस का अभाव: अपर्याप्त नगिरानी प्रणालयिँ प्रतर्किल औषधि प्रतर्किरियाओं (ADR) को ट्रैक करने और कम करने में वफिल रहती हैं, जिससे दीर्घकालकि स्वास्थय जोखमि उत्पन्न होते हैं।
 - वनियामक प्राधकिरणों के पास प्रायः सटीक समय पर औषधि सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिये संसाधनों और तंत्रों का अभाव होता है, जिसके कारण अनावश्यक जटलिताएँ उत्पन्न होती हैं।
 - यह वकिसशील देशों में वषिणन-पश्चात नगिरानी प्रणालयिँ की खराब स्थतिको भी दर्शाता है।
 - 895 प्रतर्किल दवा प्रतर्किरिया नगिरानी के बावजूद वैश्वकि ADR डेटाबेस में भारत का योगदान केवल 2% है।
 - वर्ष 2019 में, N-नाइट्रोसोडमिथाइलमाइन संदूषण के कारण रैनटिडिनि को वापस ले लिये जाने से फारमाकोवजिलिंस प्रणालयिँ में अंतराल को रेखांकति कयिा गया।
- वैश्वकि बाज़ार में प्रवेश में बाधाएँ: असंगत वनियामक फरेमवरक और मानक-नरिधारण में पारदर्शति की कमी, उभरती हुई दवा कंपनयिँ के लिये अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक अभगिम में बाधा डालती है।
 - ये बाधाएँ छोटे नरिमाताओं को अपना परचालन बढ़ाने और वैश्वकि स्तर पर प्रतर्षिप्रदधा करने से रोकती हैं।
 - अच्छे वनिरमाण प्रथाओं (GMP) का गैर-अनुपालन एक महत्त्वपूर्ण बाधा है।
 - भारत में वर्तमान में 10,500 दवा वनिरमाण इकाइयों में से केवल 19% के पास ही WHO-GMP प्रमाणन है।
 - इससे अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे वनियमति बाज़ारों में प्रवेश करने की भारत की क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
- फारमास्यूटिकल अपशषिट से पर्यावरणीय क्षतः फारमास्यूटिकल अपशषिट के अनयिमति नषिटान से गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, जिससे पारस्थितिकि तंत्र और सार्वजनिक स्वास्थय प्रभावति होता है।

- **वनिरिमाण इकाइयों से मुक्त होने वाला अपशष्टि**, वशिष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, नदियों और भूजल प्रदूषण का कारण बनता है।
 - पर्यावरणीय नियमों के लापरवाह क्रियान्वयन से यह समस्या और भी जटिल हो गई है।
- एक हालिया अध्ययन में वैश्विक नदियों के 43.5% में दवा प्रदूषकों की पहचान की गई है, जिसमें यमुना नदी सबसे प्रदूषित है।
 - भारत वैश्विक एंटीबायोटिक प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता है, जिससे AMR संकट और भी गंभीर हो गया है।
- **आवश्यक दवाओं की सुलभता में असमानताएँ**: अपर्याप्त मूल्य वनियमन और एकाधिकारवादी प्रथाओं के कारण आवश्यक दवाएँ सीमांत आबादी के लिये अप्राप्य रह जाती हैं।
 - दवा मूल्य न्यंत्रण के लापरवाह कार्यान्वयन से कंपनियों को अत्यधिक कीमतें वसूलने में मदद मिलती है, जिससे स्वास्थ्य असमानता की स्थिति और भी बदतर हो जाती है।
 - दूर-दराज़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता की कमी से समस्या और भी गंभीर हो जाती है
 - सरकारी मेडिकल स्टोर पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता ग्रामीण आबादी के लिये एक चुनौती है।
 - एक हालिया रपॉर्ट के अनुसार, केवल 12.2% प्रत्यर्थियों को (अपने गाँवों से आने-जाने योग्य दूरी के भीतर) **प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों** पर सब्सिडी वाली दवाओं की सुलभता है।
- **अनुपालन मानकों की अप्रभावीता**: खंडति और जटिल नयामक प्रणालियाँ नरिमाताओं को भ्रमति करती हैं, अनुपालन दरों को कम करती हैं तथा वैश्विक बाज़ारों में उत्पाद अस्वीकृतिको बढ़ाती हैं।
 - FSSAI, BIS और APEDA जैसी एजेंसियों के अलग-अलग मानक अनावश्यकता एवं अक्षमता उत्पन्न करते हैं। इससे भारतीय दवा उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम स्वीकार्यता होती है।

भारत में औषधिवनियमन को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **वनियामक फ्रेमवर्क को सुव्यवस्थिति करना**: भारत को ओवरलैप्स को खत्म करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये एकीकृत एवं पारदर्शी वनियामक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है।
 - CDSCO और राज्य स्तरीय नकियों जैसी एजेंसियों को एक केंद्रीकृत औषधि प्राधिकरण में वलिय करने से समन्वय एवं अनुपालन में सुधार हो सकता है।
 - इससे अनुमोदन, परीक्षण और नगिरानी प्रक्रियाओं का मानकीकरण होगा, जिससे अकुशलताएँ कम होंगी।
 - अमेरिका जैसे देशों में FDA जैसी केंद्रीकृत प्रणालियाँ हैं, जो राज्यों में दवा वनियमन और प्रवर्तन में एकरूपता सुनिश्चित करती हैं।
- **फार्माकोवजिलेंस और वणिण-पश्चात् नगिरानी को सुदृढ़ करना**: प्रतकिल दवा प्रतक्रियाओं (ADR) की नगिरानी और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार के लिये सुदृढ़ फार्माकोवजिलेंस प्रणालियों की स्थापना आवश्यक है।
 - भारतीय फार्माकोवजिलेंस कार्यक्रम (PvPI) का वसितार करके इसमें नजी अस्पतालों, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और ई-फार्मेसियों को शामिल करने से ADR रपॉर्टिंग में वृद्धि हो सकती है।
 - उन्नत डाटा वशिलेषण और AI संभावति दवा जोखमों का पहले ही अनुमान लगा सकते हैं।
- **अच्छे वनिरिमाण व्यवहार (GMP) के अनुपालन को लागू करना**: वनिरिमाण सुवधियों की आवधिक ऑडिट और रयिल टाइम मॉनटरिंग GMP मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित कर सकती है।
 - उल्लंघन के लिये कठोर दंड तथा अनुपालन के लिये प्रोत्साहन लागू करने से उत्तरदायित्व को बढ़ावा मलिया।
 - दवा पैकेजिंग पर QR कोड लागू करने से आपूर्ति शृंखला में अनुपालन का पता लगाने और सत्यापन में मदद मल सकती है।
- **पारदर्शिता के लिये राष्ट्रीय औषधि डेटाबेस का नरिमाण**: अनुमोदति औषधियों, नरिमाताओं और नयामक स्थतियों को सूचीबद्ध करने वाला एक केंद्रीकृत, सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटाबेस पारदर्शिता को बढ़ा सकता है।
 - इससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं को दवा की प्रामाणिकता सत्यापति करने तथा अस्वीकृत या नकली उत्पादों की बकिरी को रोकने में मदद मलिया।
 - ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने से डेटा इंटीग्रिटी को और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है।
- **नयामक क्षमता और बुनियादी अवसंरचना में सुधार**: उन्नत परीक्षण प्रयोगशालाओं, कुशल कार्यबल और डिजिटल उपकरणों में नविश से भारत की नयामक क्षमता सुदृढ़ होगी।
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन के अंतर्गत वनियामक बुनियादी अवसंरचना के लिये धन आवंटति करने से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अंतराल को कम किया जा सकता है।
 - नयामक कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं में नयिमति प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सामंजस्य**: भारत को अपने औषधिमानकों को अमेरिकी FDA और यूरोपीय औषधि एजेंसी (EMA) जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।
 - मानकों की पारस्परिक मान्यता के लिये द्वपिक्षीय समझौतों से नरियात अस्वीकृतियों में कमी आ सकती है तथा बाज़ार पहुँच में वृद्धि हो सकती है।
 - नरियात प्रमाणन के लिये "एकल खडिकी अनुमोदन प्रणाली" शुरू करने से अनुमोदन को सुचारु बनाया जा सकता है।
- **नैतिक नैदानिक परीक्षणों और अनुसंधान एवं वकिस नरीक्षण को प्रोत्साहित करना**: नैदानिक परीक्षणों के लिये सख्त दशान-नरिदेश, साथ ही रयिल टाइम मॉनटरिंग, नैतिक प्रथाओं और रोगी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं।
 - AI-सक्षम नगिरानी उपकरणों के साथ एक राष्ट्रीय नरीक्षण समति की स्थापना प्रभावी रूप से परीक्षण अनुपालन को ट्रैक कर सकती है। नैतिक अनुसंधान एवं वकिस के लिये कर छूट जैसे प्रोत्साहन नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **ऑनलाइन फार्मेसियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को वनियमति करना**: नकली और बनि लाइसेंस वाली दवाओं की बकिरी पर अंकुश लगाने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्मों को सख्त नयामक नगिरानी के तहत लाया जाना चाहिये।
 - ई-फार्मेसियों का अनविर्य पंजीकरण और उन्हें आधार-सक्षम सत्यापन प्रणालियों से जोड़ने से जवाबदेही में सुधार हो सकता है।
 - AI उपकरण ऑनलाइन लेनदेन में अनयिमतिताओं की नगिरानी कर सकते हैं।

- **संवहनीय औषधि प्रथाओं को प्रोत्साहित करना:** हरति वनिरिमाण प्रथाओं को अपनाने से औषधि अपशष्टि से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सकता है।
 - अपशष्टि उपचार मानदंडों का सख्ती से पालन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिये सब्सिडी अनुपालन को बढ़ावा दे सकती है।
 - **CPCB और MoEFCC** जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग करके पर्यावरणीय दशानरिदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **जन-जागरूकता और उपभोक्ता सशक्तीकरण का निर्माण:** उपभोक्ताओं को सुरक्षित दवा उपयोग के बारे में शक्ति करना, नकली दवाओं की पहचान करना और प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्ट करना आवश्यक है।
 - जनसंचार माध्यमों, स्कूलों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से **सार्वजनिक अभियान जागरूकता बढ़ा सकते हैं।** मादक पदार्थों दवाओं से संबंधित शिकायतों के लिये एक **टोल-फ्री हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप** उपभोक्ताओं को सशक्त बना सकता है।
 - भारत में **"[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]"** अभियान शुरू किया जा सकता है, जिससे अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित होगी।
- **क्षेत्रीय औषधि वनियमन केंद्रों का विकास:** उन्नत प्रयोगशालाओं और वनियामक कार्यालयों वाले क्षेत्रीय केंद्र नगिरानी को वकिंदरति कर सकते हैं और दक्षता में सुधार कर सकते हैं।
 - ये केंद्र वंचति क्षेत्रों में दवा परीक्षण, नरीक्षण और नगिरानी जैसी वशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
 - इससे समय पर क्रयान्वयन सुनिश्चित होगा और केंद्रीय एजेंसियों पर बोझ कम होगा।
- **आपूर्ति शृंखला पारदर्शिता के लिये ब्लॉकचेन का अंगीकरण:** ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी दवा आपूर्ति शृंखला की **इंड-टू-इंड वजिबिलिटी** सुनिश्चित कर सकती है, जिससे नकली दवाओं को बाजार में प्रवेश करने से रोका जा सकता है।
 - यह प्रौद्योगिकी **उत्पाद की ट्रेसेबिलिटी** को भी बढ़ा सकती है, जिससे **प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता और अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा।**
 - सरकार समर्थति ब्लॉकचेन प्रणाली हतिधारकों का वशिवास बढ़ा सकती है।
- **ठीक समय पर औषधि वापसी तंत्र का निर्माण:** भारत को नमिन स्तरीय या हानिकारक औषधियों को प्रचलन से शीघ्र हटाने के लिये एक **दृढ़, प्रौद्योगिकी-सक्षम औषधि रिकॉल प्रणाली** की आवश्यकता है।
 - **नरिमाताओं, थोक वकिरेताओं और खुदरा वकिरेताओं** से जुड़ी एक केंद्रीकृत चेतावनी प्रणाली तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर सकती है। नियमति मॉक ड्रलि बड़े पैमाने पर रिकॉल के लिये तत्परता बढ़ा सकती है।
- **प्रदर्शन-आधारति नरिमाता प्रमाणन की शुरुआत:** प्रदर्शन-आधारति प्रमाणन प्रणाली नरिमाताओं को उच्च गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है।
 - GMP, पर्यावरण मानकों और नवाचार अनुपालन पर आधारति रैकिंग द्वारा स्वस्थ प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जा सकता है।
 - मान्यता मानदंडों के नियमति अद्यतन से प्रथाओं को वैश्विक प्रगत के साथ संरेखति किया जा सकता है।

नषिकर्ष:

भारत में दवा वनियमन को सुदृढ़ करना **स्वास्थ्य सेवा में सामर्थ्य और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक** है। एक एकीकृत वनियामक फ्रेमवर्क, बेहतर **फार्माकोवजिलेंस और वनिरिमाण मानकों के साथ सख्त अनुपालन** दवा सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय वशि्वसनीयता को बढ़ाएगा। पारदर्शिता, तकनीकी प्रगत एवं संवाहनयिता पर जोर देने से भारत के दवा क्षेत्र को और बढ़ावा मलि सकता है। सक्रयि सुधारों के साथ **भारत घरेलू स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।**

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]

प्रश्न. भारत में दवाओं की गुणवत्ता, मूल्य नरिधारण और उपलब्धता सुनिश्चित करने में वनियामक नकियायों और नीतियों की भूमिका का परीक्षण कीजयि। मौजूदा वनियामक फ्रेमवर्क के आलोक में दवा उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]

प्रश्न. भैषजकि कंपनयिों के द्वारा आयुर्वजिज्ञान के पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराने से भारत सरकार कसि प्रकार रक्षा कर रही है? (2019)